कोविड-19 और भारत में एमएसएमई समूहों का प्रदर्शन

*राजीब दास, धन्या वी, अमरेंद्र आचार्य, रमेश गोलाइत, सीलू मुंडुलि और अरजित शिवहरे^*

कोविड-19 महामारी ने एमएसएमई क्षेत्र सहित भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। चुनिंदा एमएसएमई क्लस्टरों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, यह आलेख एमएसएमई क्षेत्र के प्रदर्शन और औपचारिकता की स्थिति की जांच करता है। बिजली, किराया और ऋण सेवा से संबंधित व्यय महामारी के बाद की अवधि में एमएसएमई के निवल लाभ मार्जिन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बनकर उभरे हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा तरलता और विनियामक उपायों और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) जैसी सरकारी योजनाओं ने महामारी के बाद इन उद्यमों का समर्थन किया। इस शोध पत्र के अवलोकन और परिणाम पूरे एमएसएमई क्षेत्र के लिए जरूरी नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान अध्ययन नमूना क्लस्टरों के भीतर एमएसएमई फर्मों तक सीमित है और क्लस्टरों के बाहर फर्मों की विशेषताएं और व्यवहार अलग हो सकते हैं।

परिचय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) दुनिया भर में व्यवसाय उद्यमों के जाने-माने रूप हैं, जिनमें छोटे आकार, स्वतंत्र संस्थाएँ और सीमित बाज़ार जोखिम जैसी विशेषताएँ हैं। एमएसएमई उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर और तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर रोज़गार पैदा करके समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कोविड महामारी ने भारत सहित विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए व्यापार परिदृश्य को बाधित कर दिया। जवाब में, भारत सरकार (जीओआई) और रिज़र्व बैंक ने सामान्य मौद्रिक और राजकोषीय सहायता उपायों के अलावा, एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने और व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नीतियाँ पेश कीं। महामारी के कम होने के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था ने बाद की अवधि में अपनी रिकवरी शुरू की।

भारत में इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा दशकों से विभिन्न नीतिगत उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख है एमएसएमई विकास के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण। भारत में एमएसएमई का एक बड़ा हिस्सा सूक्ष्म श्रेणी में आता है, जो अपने संचालन में अधिक गंभीर चुनौतियों का सामना करता है। फर्म की 'लघुता' से उत्पन्न सीमाओं को दूर करने के लिए नीति उपकरण के रूप में एमएसएमई विकास के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण की अवधारणा की गई थी। क्लस्टर कई रास्तों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु फर्मों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से कच्चे माल की निकटता, उपयुक्त व्यवसाय विकास सेवाएं, विपणन सुविधाएं और कुशल श्रम (क्रुगमैन, 1991) के माध्यम से। भारत में क्लस्टर दृष्टिकोण की ओर पहला कदम 1998 में छोटे उद्योगों में प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ शुरू हुआ।

इस पृष्ठभूमि में, चुनिंदा एमएसएमई क्लस्टरों के बीच किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित यह अध्ययन एमएसएमई फर्मों के प्रदर्शन और महामारी के दौरान शुरू किए गए नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता की जांच करता है। यह एमएसएमई फर्मों की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों और कोविड महामारी से पहले और बाद में उनकी परिवर्तनशीलता का भी विश्लेषण करता है।

यह शोध पत्र चार खंडों में संरचित है, जिसकी शुरुआत परिचय से होती है। खंड II एमएसएमई क्षेत्र की स्थिति प्रस्तुत करता है, जिसमें परिभाषा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए नीतिगत उपाय शामिल हैं। खंड III डेटा आधारित विश्लेषण करता है, सर्वेक्षण पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है और स्थापित तथ्य प्रस्तुत करता है। खंड IV समापन टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है।

^ लेखक-गण, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), मुंबई से हैं। लेखक-गण, सौम्या भादुरी और डी. सुगांति को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देते हैं। आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

II. भारत में एमएसएमई की स्थिति

II.1 परिभाषा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एमएसएमई क्षेत्र में काफी विविधता है, जो उद्यम के आकार, पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की श्रेणी और उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी के स्तर में भिन्नताओं की विशेषता है। एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार, एमएसएमई को शुरू में संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण निवेश सीमाओं के संदर्भ में परिभाषित किया गया था। हालांकि, उनके अनौपचारिक और छोटे पैमाने के संचालन के कारण, निवेश मानदंडों के आधार पर एमएसएमई को वर्गीकृत करना मुश्किल माना जाता था (आरबीआई, 2019)। 2020 में, भारत सरकार ने मशीनरी और उपकरणों में निवेश के आधार पर पहले के मानदंड के साथ-साथ टर्नओवर को भी एक मानदंड के रूप में शामिल किया। 2017 में माल और सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत ने माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) डेटा से टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण को सत्यापित करने का एक तरीका प्रदान किया, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आई। इसके अलावा, विनिर्माण और सेवाओं के बीच का अंतर हटा दिया गया। एमएसएमई के दायरे को व्यापक बनाने के लिए निर्यात को भी टर्नओवर वर्गीकरण से बाहर रखा गया। तदनुसार, वर्तमान में:

i. उद्यम एक सूक्ष्म उद्यम है, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश अधिकतम ₹1 करोड़ है, और कारोबार अधिकतम ₹5 करोड़ है।

ii. एक छोटा उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश ₹10 करोड़ से अधिक नहीं है, और कारोबार ₹50 करोड़ से अधिक नहीं है; और

iii. एक मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश अधिकतम ₹50 करोड़ है, और कारोबार ₹250 करोड़ से अधिक नहीं है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण, अक्टूबर 2022-सितंबर 2023 के अनुसार, भारत में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगे लगभग 6.5 करोड़ असंगठित गैर-कृषि एमएसएमई हैं। हालांकि, सितंबर 2024 तक एमएसएमई के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल उद्यम पोर्टल में केवल 5.2 करोड़ एमएसएमई इकाइयां पंजीकृत थीं। एनएसएसओ के अनुसार, अक्टूबर 2022-सितंबर 2023 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र ने लगभग 11 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिया, जो अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार का लगभग पाँचवाँ हिस्सा और गैर-कृषि रोजगार का 35 प्रतिशत है। एमएसएमई उच्च आय और उच्च-मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 63-66 प्रतिशत रोजगार, निम्न-मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं में कुल रोजगार का 91 प्रतिशत और निम्न आय अर्थव्यवस्थाओं में 81 प्रतिशत रोजगार में योगदान करते हैं (हैदर और अन्य, 2019)।

भारत में एमएसएमई मोटे तौर पर 'सूक्ष्म श्रेणी' में आते हैं और प्रौद्योगिकी अपनाने, ऋण उपलब्धता, बुनियादी ढांचे और औपचारिकता (आरबीआई, 2019) में चुनौतियों का सामना करते हैं। जबकि उत्पादकता पर फर्म के आकार के प्रभाव पर निर्णायक साक्ष्य का अभाव है, फर्मों की 'छोटी प्रकृति' एमएसएमई को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने से रोक सकती है (विलियमसन, 1967; उटरबैक, 1994; धवन, 2001)। मध्यम और बड़ी फर्में छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक नवोन्मेषी होती हैं (भारत सरकार, 2014)। अपर्याप्त कुशल श्रम, सीमित वित्तपोषण, तकनीकी और बाजार की जानकारी की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा एमएसएमई फर्मों द्वारा नवाचारों के लिए बाधाएँ हैं (भारत सरकार, 2014; पचौरी और शर्मा, 2016)।

माइकल पोर्टर (पोर्टर, 1990; पोर्टर, 1998) द्वारा अग्रणी आर्थिक विकास के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण ने 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में छोटे स्वतंत्र इकाइयों के सामने आने वाली सीमाओं को दूर करने के लिए देशों में गति प्राप्त की। क्लस्टर दृष्टिकोण को व्यापक महत्व तब मिला जब संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) ने 2003 में इसे औद्योगिक विकास रणनीतियों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महत्व दिया और बताया कि क्लस्टर में व्यापक-आधारित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है (यूएनआईडीओ, 2020)। एमएसएमई क्लस्टर संबद्ध संस्थानों और परस्पर जुड़ी कंपनियों के समीपवर्ती समूह हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में साझा प्रौद्योगिकियों और विशेषज्ञता

से बंधे हैं। आमतौर पर, क्लस्टर भौगोलिक रूप से इस प्रकार स्थित होते हैं कि निर्बाध संचार, संभार-तंत्र और पारस्परिक संपर्क की सुविधा मिलती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है, जो विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है (पोर्टर, 2003)।

क्लस्टरों की प्रभावशीलता विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, विपणन और खरीद जैसी विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं में छोटी व्यक्तिगत फर्मों के बीच संसाधनों के सहयोगात्मक साझाकरण पर निर्भर करती है। क्लस्टर और संबंधित नेटवर्क छोटी फर्मों को बड़ी इकाइयों के बराबर पैमाने और विशेषज्ञता की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक छोटी इकाई चलाने के लाभों को संयोजित करने में सक्षम बनाते हैं (मैगर, 2017)।

भारत में लघु उद्योग (एसएसआई) विकास के लिए केंद्र बिंदु के रूप में क्लस्टरों का प्रारंभिक आधिकारिक समर्थन आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट (जीओआई, 1997) से आया था। भारत ने एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और वृद्धि को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए 2003 से सक्रिय रूप से क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाया है। एमएसएमई मंत्रालय ने क्लस्टरों को *"एक पहचान योग्य और जहां तक संभव हो, सन्निहित क्षेत्र या मूल्य श्रृंखला के भीतर स्थित उद्यमों के समूह के रूप में परिभाषित किया है जो भौगोलिक क्षेत्र से परे जाते हैं और समान/समान/पूरक उत्पाद/सेवाएं बनाते हैं, जिन्हें सामान्य भौतिक अवसंरचना सुविधाओं द्वारा एक साथ जोड़ा जा सकता है जो उनकी सामान्य चुनौतियों का समाधान करने में मदद करते हैं। एक क्लस्टर में उद्यमों की आवश्यक विशेषताएं हैं (ए) उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण, ऊर्जा खपत, प्रदूषण नियंत्रण आदि के तरीकों में समानता या पूरकता, (बी) प्रौद्योगिकी और विपणन रणनीतियों/प्रथाओं का समान स्तर, (सी) क्लस्टर के सदस्यों के बीच संचार के लिए समान चैनल, (डी) सामान्य बाजार और कौशल की जरूरतें और (ई) क्लस्टर के सामने आने वाली सामान्य चुनौतियां और अवसर।"* [1] क्लस्टर पहलों को कुशल नीति उपकरण के रूप में मान्यता दी गई, जिससे विकास और वृद्धि की काफी संभावना वाले विशिष्ट क्षेत्रों में संसाधनों और निधियों का केंद्रित आवंटन संभव हो सका। यह लक्षित दृष्टिकोण संभावित स्पिलओवर और गुणक प्रभावों के कारण लाभप्रद है जो आरंभिक रूप से पहचाने गए स्थानों से आगे तक फैल सकते हैं। इंडिया क्लस्टर ऑब्जर्वेटरी के अनुसार, सितंबर 2024 में भारत में 4361 क्लस्टर थे, जिनमें से 57.2 प्रतिशत क्लस्टर हस्तशिल्प क्षेत्र से संबंधित थे, इसके बाद 30 प्रतिशत औद्योगिक क्लस्टर और 13 प्रतिशत हथकरघा क्लस्टर थे।

II.2 नीतिगत उपाय

एमएसएमई मंत्रालय ने 1998 में औद्योगिक क्लस्टरों में चुनिंदा हस्तक्षेप शुरू किए और उसके बाद क्षमता निर्माण, विपणन विकास, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास और सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से अपने एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम को व्यापक बनाया। एमएसएमई मंत्रालय ने पारंपरिक खादी और ग्रामोद्योगों के लिए विशेष रूप से पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना (एसएफयूआरटीआई) भी शुरू की है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 2003 में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) की शुरुआत की, जो विशिष्ट परिचालन क्लस्टरों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम करके उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी।

सरकार ने 2007 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) को भी संशोधित किया। यह मांग-संचालित केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में संचालित होता है, जिसमें राज्य सरकारें सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की शुरुआत/उन्नयन के लिए प्रस्ताव भेजती हैं। एमएसई-सीडीपी योजना ने क्लस्टर के भीतर सदस्य और गैर-सदस्य इकाइयों की मूल्य श्रृंखला को प्रभावी ढंग से बढ़ाया और मजबूत किया है, जिसके कारण लगभग 10-15 प्रतिशत की कुल उत्पादकता में वृद्धि

[1] https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/COM_ClusterForm.aspx

हुई है, विनिर्माण लागत में भी इसी तरह की कमी आई है और परिचालन दक्षता में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है[2]।

एमएसएमई को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए, 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की गई थी, जिसने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को संपार्श्विक मुक्त ऋण सक्षम करने के लिए वित्तीय संस्थानों को ऋण गारंटी सहायता प्रदान की। 2017 में, इस योजना को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को इस योजना में शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया था, जो एमएसई को ऋण संवितरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं (एनबीएफसी के लिए क्रेडिट गारंटी योजना - सीजीएस-II)।

एमएसएमई को भुगतान में देरी की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 2014 में ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) की शुरुआत की थी। टीआरईडीएस एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जहां एमएसएमई बड़ी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), सरकारी विभागों, आदि सहित खरीदारों से छूट पर अपने प्राप्तियों का वित्तपोषण सुरक्षित कर सकते हैं।

एमएसएमई पर कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई को ऋण और तरलता तक निरंतर पहुंच प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं, ताकि इस क्षेत्र की व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) को 2020 में शुरू किया गया था, ताकि दबावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों को इक्विटी, अर्ध इक्विटी या उप-ऋण के रूप में ऋण दिया जा सके। इसके अलावा, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स एटीएम के तहत निर्भार निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत, शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया गया। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) भी 2020 में शुरू की गई थी, जो पूरी तरह से गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन के माध्यम से एमएसएमई को अतिरिक्त धन मुहैया कराती है। आरबीआई ने 9 अक्टूबर, 2020 को ऑन-टैप लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) योजना शुरू की, ताकि बैंक एमएसएमई सहित कई क्षेत्रों को तरलता सहायता प्रदान कर सकें। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देशों के अधीन ऋण स्थगन की अनुमति दी और बैंकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पहली बार ऋण लेने वालों को वितरित ऋणों के विरुद्ध नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की आवश्यकता रखने से छूट दी। 2022 में, आरबीआई की सह-उधार नीतियों के अनुरूप, सीजीटीएमएसई ने बैंकों और एनबीएफसी द्वारा संयुक्त रूप से सह-उधार मॉडल के तहत ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी कवरेज बढ़ाने के लिए सह-उधार के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएससीएल) शुरू की।

III. स्थापित तथ्य और डेटा आधारित विश्लेषण

III.1 सर्वेक्षण पद्धति और कवरेज

यह अध्ययन अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 110 क्लस्टरों के बीच किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित है। एमएसएमई फर्मों का चयन यूएनआईडीओ क्लस्टरों की सूची और राज्य सरकारों की एमएसएमई क्लस्टरों की सूचियों में पहले से पहचाने गए क्लस्टरों से किया गया था। प्रत्येक क्लस्टर से, फर्मों का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया था। अध्ययन के लिए कुल 3,246 एमएसएमई का साक्षात्कार लिया गया (सारणी 1)।

सारणी 1: राज्यों में नमूने का वितरण

राज्य	सर्वेक्षण किये गये एमएसएमई की संख्या	हिस्सा (प्रतिशत)
पश्चिम बंगाल	625	19.3
दिल्ली	557	17.2
महाराष्ट्र	376	11.6
पंजाब	353	10.9
गुजरात	240	7.4
तमिलनाडु	203	6.3
कर्नाटक	194	6
उतार प्रदेश	159	4.9
राजस्थान	104	3.2
ओडिशा	93	2.9
आंध्र प्रदेश	81	2.5
तेलंगाना	81	2.5
झारखंड	61	1.9
मध्य प्रदेश	53	1.6
हरयाणा	46	1.4
असम	20	0.6
कुल	3246	100

स्रोत: सर्वेक्षण पर आधारित लेखकों का अनुमान।

[2] सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का मूल्यांकन अध्ययन - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद।

सारणी 2: उद्योग समूहों में नमूना फर्मों का वितरण

एनआईसी 2008	उद्योग	प्रतिक्रिया की संख्या	हिस्सा (प्रतिशत)
27	विद्युत उपकरण	460	14.2
14	पहनने के परिधान	280	8.6
15	चमड़ा	278	8.6
29	मोटर वाहन	258	7.9
24	मूल धातुएं	247	7.6
13	वस्त्र	210	6.5
28	मशीनरी	192	5.9
17	कागज़ और कागज़ उत्पाद	158	4.9
10	खाद्य उत्पाद	149	4.6
22	रबर और रबर उत्पाद	149	4.6
20	रासायनिक और रासायनिक उत्पाद	139	4.3
25	गढ़े हुए धातु उत्पाद	118	3.6
26	कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक	113	3.5
21	दवाइयों	110	3.4
23	अन्य धात्विक अखनिज	104	3.2
16	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	99	3.0
32	अन्य विनिर्माण	85	2.6
31	फर्नीचर	80	2.5
1	फसलें और पशु	17	0.5
	कुल	**3246**	**100**

स्रोत: सर्वेक्षण पर आधारित लेखकों का अनुमान।

सर्वेक्षण की गई फर्मों को तुलना में आसानी के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 के आधार पर 18 विनिर्माण उप-क्षेत्रों और एक कृषि क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत उपकरण बनाने वाली फर्मों का नमूने में सबसे बड़ा हिस्सा था, उसके बाद परिधान, चमड़ा उद्योग, मोटर वाहन, आधार धातु और वस्त्र (सारणी 2) का स्थान था। चूंकि इस अध्ययन में सर्वेक्षण में केवल नमूना समूहों के भीतर एमएसएमई फर्मों को शामिल किया गया था, इसलिए सर्वेक्षण के जवाब और इस शोध पत्र में अवलोकन और विश्लेषण व्यापक एमएसएमई क्षेत्र के लिए लागू नहीं होते हैं।

III.2 स्थापित तथ्य

III.2.1 निगमीकरण

भारत ने एमएसएमई के निगमीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इनमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण और जीएसटी नेटवर्क का हिस्सा बनना जैसी पहल शामिल हैं।

सैंपल किए गए क्लस्टरों में से लगभग तीन-चौथाई निजी क्षेत्र के थे, उसके बाद सहकारी और राज्य सरकार के क्लस्टर थे। सर्वेक्षण की गई फर्मों में से एक-पांचवां हिस्सा सूचीबद्ध था और 95 प्रतिशत के पास बैंक खाते थे। तीन-चौथाई से अधिक उद्यम सूक्ष्म-उद्यम श्रेणी के थे, जबकि छोटी और मध्यम फर्मों की हिस्सेदारी क्रमशः कुल फर्मों में 14 प्रतिशत और 2 प्रतिशत थी। 2022-23 में बिक्री औसतन ₹4.4 करोड़ रही जो ₹70,000 से ₹250 करोड़ के बीच थी। लगभग 70 प्रतिशत फर्मों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है और वे अपने व्यावसायिक संचालन के लिए इसका उपयोग करती हैं।

सर्वेक्षण में शामिल लगभग 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जो एमएसएमई इकाइयों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन मंच है। आकार के हिसाब से, सर्वेक्षण में शामिल मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों में से क्रमशः 98, 84 और 69 प्रतिशत उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। 10 से अधिक कर्मचारियों वाली 80 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता एमएसएमई इकाइयों ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है । उत्तरदाता एमएसएमई इकाइयों में से आधे से अधिक ईपीएफओ और ईएसआईसी (चार्ट 1) के साथ पंजीकृत हैं।

III.2.2 बैंकिंग और वित्त तक पहुंच

सर्वेक्षण के आधार पर, एमएसएमई फर्मों का बहुमत बैंक से जुड़ा हुआ पाया गया है, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयां अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से करती हैं। लगभग 98 प्रतिशत मध्यम उद्यमों ने कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे वेतन जमा किया। सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह अनुपात लगभग 67 प्रतिशत कम है (चार्ट 2ए और 2बी)।

सर्वेक्षण के अनुसार, एमएसएमई फर्मों ने अपने उद्यमों के खर्चों का प्रबंधन करने के लिए ज़्यादातर व्यक्तिगत बचत, व्यापार ऋण और प्रतिधारित आय का इस्तेमाल किया।

चार्ट 1: उद्यम और ईपीएफओ के साथ पंजीकरण

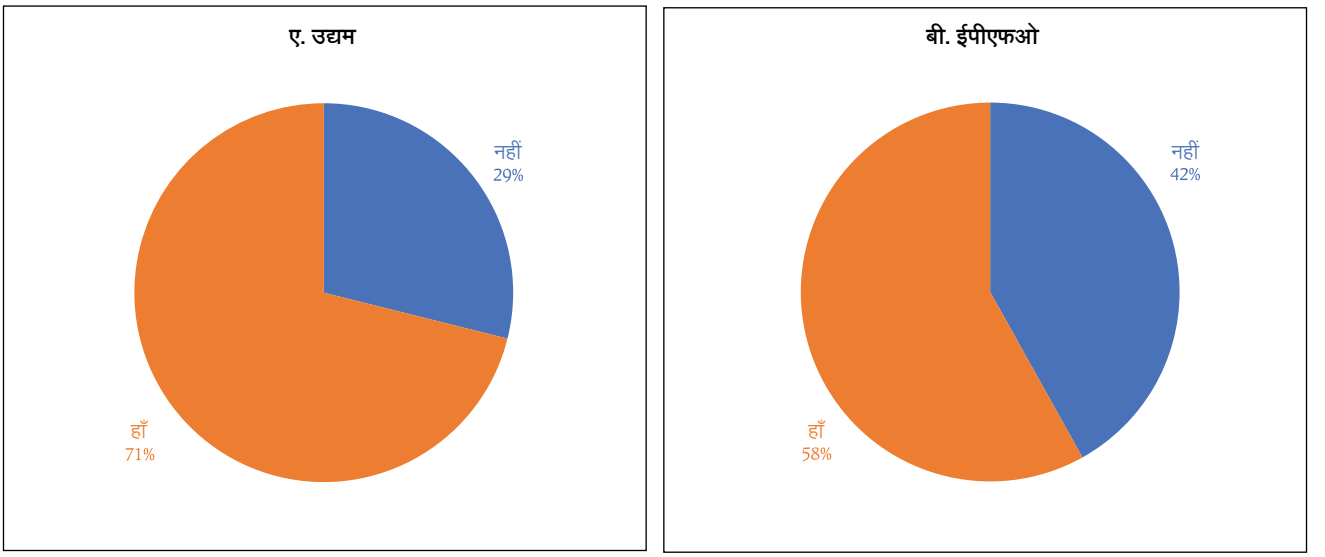

स्रोत: सर्वेक्षण पर आधारित लेखकों का अनुमान।[3]

हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहे स्रोतों पर नज़र डालें तो सर्वेक्षण के अनुसार व्यक्तिगत बचत वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत पाया गया, इसके बाद व्यापार ऋण, प्रतिधारित आय, मित्र और रिश्तेदार, बैंक ऋण और धन उधारदाता आते हैं। लगभग 42.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यक्तिगत बचत को महामारी के बाद वित्तपोषण के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा, जबकि महामारी से पहले यह अनुपात 32 प्रतिशत था। जबकि व्यक्तिगत बचत सबसे पसंदीदा स्रोत बनी रही, व्यापार ऋण, प्रतिधारित आय और बैंक ऋण का महत्व महामारी के बाद बढ़ गया क्योंकि क्रमशः 12.7 प्रतिशत, 11.5 प्रतिशत और 11.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी शीर्ष प्राथमिकता इन श्रेणियों को दी (चार्ट 3)।

चार्ट 2: बैंक खातों के माध्यम से वेतन का भुगतान

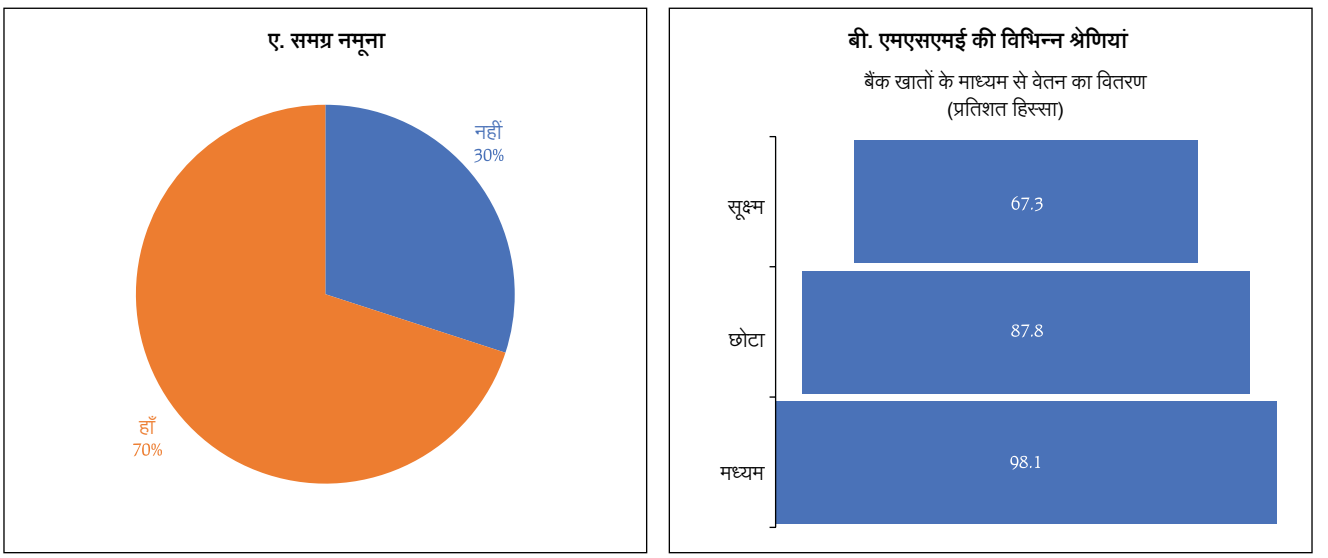

स्रोत: सर्वेक्षण पर आधारित लेखकों का अनुमान।

[3] सर्वेक्षण प्रश्न था: "क्या कंपनी उद्यम पोर्टल में पंजीकृत है? क्या कर्मचारी ईपीएफओ में पंजीकृत हैं?" विस्तृत प्रश्न प्रश्नावली (अनुबंध) में दिए गए हैं।

चार्ट 3: वित्तपोषण के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत

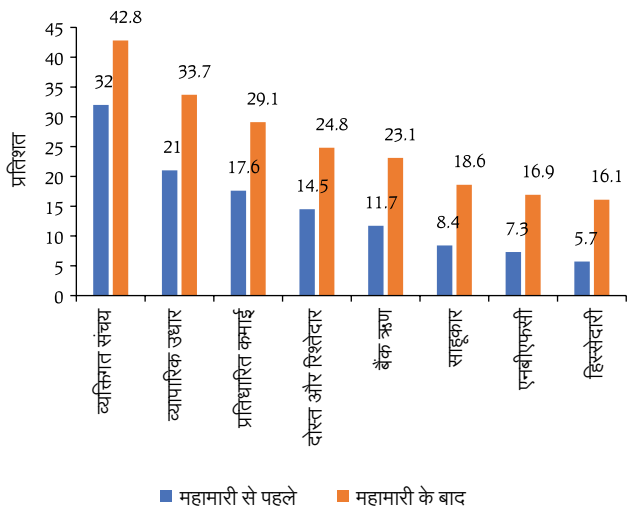

टिप्पणी : इन संख्याओं का योग 100 होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक ही फर्म ने वित्तपोषण के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अनेक स्रोत बताए हैं।
स्रोत : सर्वेक्षण पर आधारित लेखकों का अनुमान।

चार्ट 5: स्रोत-वार ऋण की मात्रा

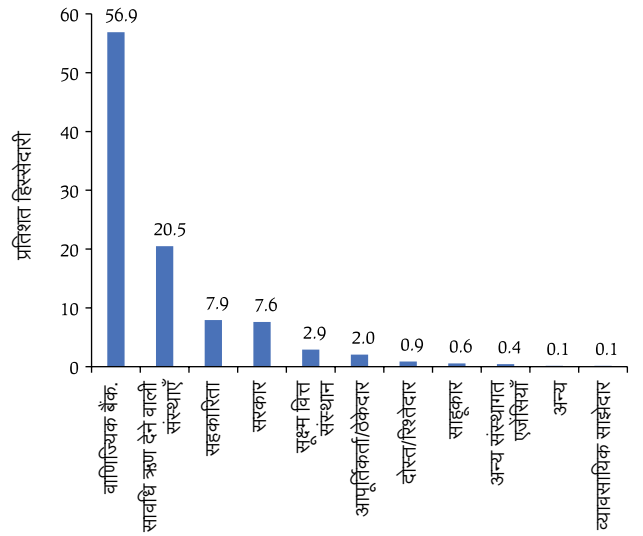

स्रोत : सर्वेक्षण पर आधारित लेखकों का अनुमान।

लगभग 80 प्रतिशत ऋण संस्थागत स्रोतों से लिए गए हैं, जिनमें से 96 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से प्राप्त हुए हैं (चार्ट 4 और 5)। वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋणों का बकाया ऋणों में महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम खंडों में सही है। फर्मों के एक बड़े हिस्से ने अपनी परिसंपत्तियों/व्यवसायों का बीमा कराया है। प्रश्न का उत्तर देने वाली 90 प्रतिशत फर्मों में से 73 प्रतिशत ने अपनी परिसंपत्तियों का बीमा कराया था।

III.2.3 एमएसएमई के सामने आने वाले व्यावसायिक और आर्थिक मुद्दे

विभिन्न बाधाओं के सापेक्ष महत्व पर, अन्य फर्मों से प्रतिस्पर्धा कोविड-पूर्व और कोविड-पश्चात दोनों अवधियों[4] में फर्मों द्वारा सामना किया जाने वाला प्रमुख व्यावसायिक मुद्दा

चार्ट 4: स्रोत-वार ऋणों की संख्या

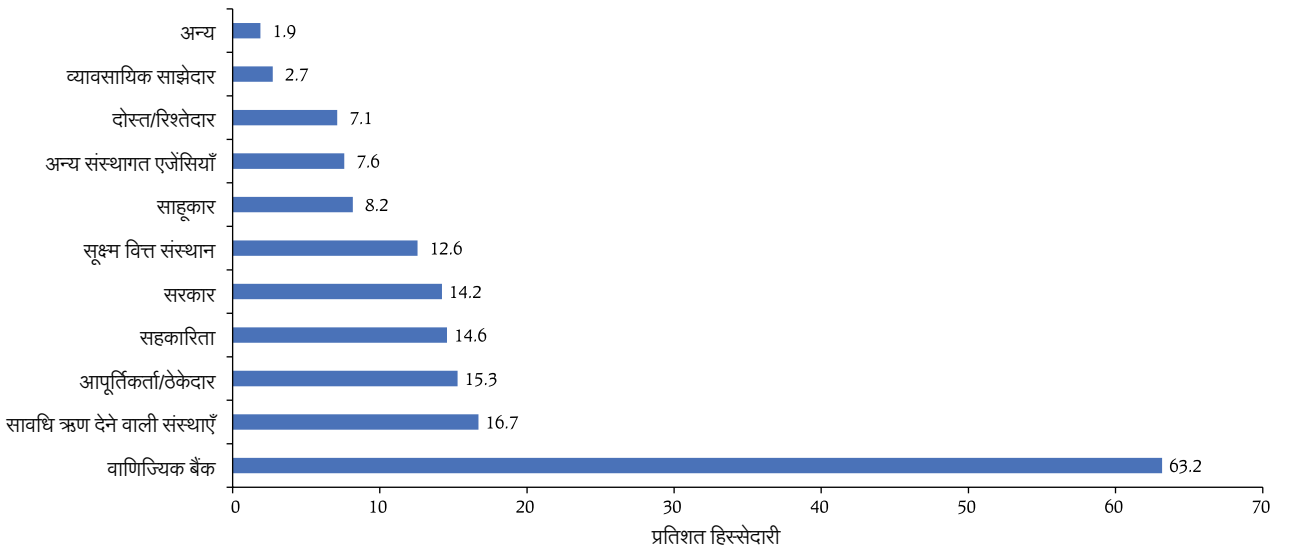

टिप्पणी : शेयरों का योग 100 नहीं होगा, क्योंकि एक ही उधारकर्ता ने अनेक स्रोतों से उधार लिया हो सकता है।
स्रोत : सर्वेक्षण पर आधारित लेखकों का अनुमान।

[4] विश्लेषण में कोविड-पूर्व अवधि, 2019-20 और कोविड-पश्चात अवधि, 2022-23 मानी गई है।

चार्ट 6: व्यावसायिक समस्याओं का संक्रमण-कोविड-पूर्व से कोविड-पश्चात तक

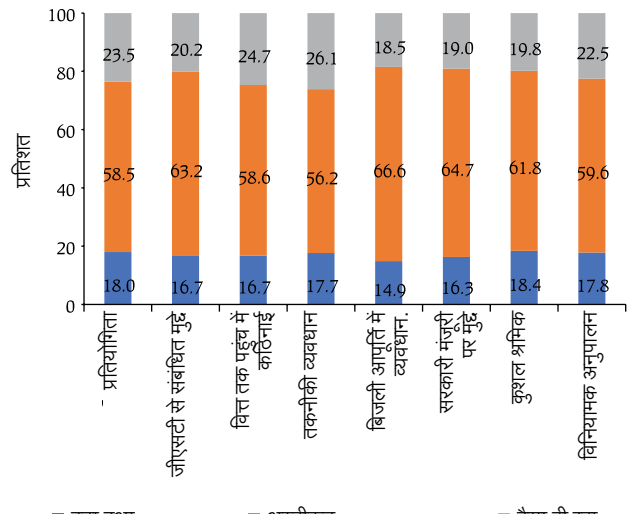

स्रोत : सर्वेक्षण पर आधारित लेखकों का अनुमान।

बन गया, जिसके बाद जीएसटी-संबंधी मुद्दे और बिजली आपूर्ति में व्यवधान थे। अधिकांश फर्मों द्वारा सरकारी मंजूरी और विनियामक अनुपालन को प्रबंधनीय व्यावसायिक मुद्दों के रूप में देखा गया जो क्लस्टर में विनियमों और अनुपालन कार्यों का पालन करने में आसानी को दर्शाता है। फर्मों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न व्यावसायिक मुद्दों में से, 23.5 प्रतिशत ने कोविड-पश्चात अवधि4 में अन्य फर्मों से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि देखी, जबकि 18 प्रतिशत फर्मों ने इसमें गिरावट देखी। अधिकांश फर्मों के लिए, कोविड-पूर्व और कोविड-पश्चात अवधि के लिए मुद्दों का सापेक्ष महत्व समान रहा, जो इन मुद्दों की संरचनात्मक प्रकृति की ओर इशारा करता है (चार्ट 6)।

बढ़ती इनपुट कीमतों के बीच उत्पादन की कीमतों को कम करने का दबाव कोविड से पहले और बाद की अवधि के दौरान फर्मों द्वारा सामना किया जाने वाला प्रमुख आर्थिक मुद्दा था। लगभग एक-चौथाई फर्मों ने इनपुट कीमतों, श्रम लागतों में वृद्धि और उत्पादन की कीमतों को कम करने के दबाव का सामना किया। विदेशी प्रतिस्पर्धा और विनिमय दर सबसे कम महत्वपूर्ण मुद्दे थे, क्योंकि अधिकांश उत्तरदाता फर्म घरेलू-उन्मुख थे। अधिकांश फर्मों के लिए, मुद्दों का सापेक्ष महत्व महामारी से पहले और बाद की अवधि के दौरान समान रहा (चार्ट 7)।

III.2.4 बुनियादी सुविधाएं

किसी क्लस्टर में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और विपणन सुविधाएं फर्मों के संचालन और लाभप्रदता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भौतिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में, सभी क्लस्टर अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। सभी उत्तरदाता फर्मों की 2 किलोमीटर के भीतर सड़कों तक पहुंच है। लगभग 62 प्रतिशत के पास 5 किलोमीटर के दायरे में गोदाम है, जबकि केवल 1.3 प्रतिशत के पास कोई गोदाम सुविधा नहीं है। गैर-प्रतिक्रिया फर्मों

चार्ट 7: उत्तरदाताओं द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे

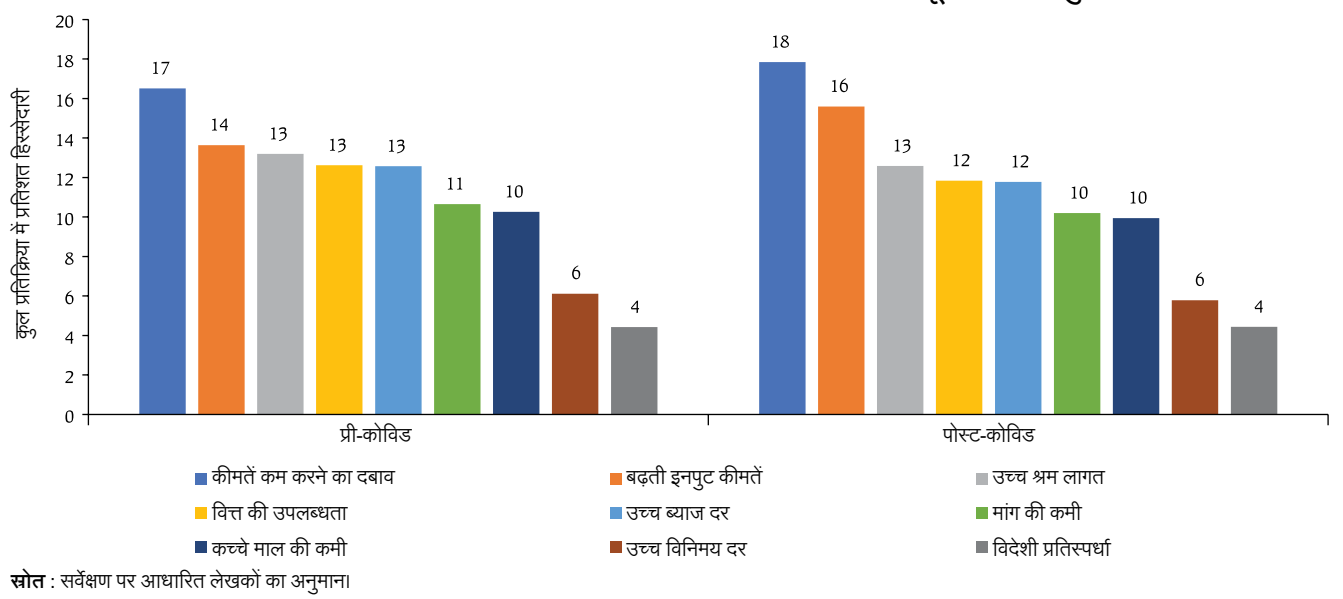

स्रोत : सर्वेक्षण पर आधारित लेखकों का अनुमान।

चार्ट 8: सब्सिडी प्राप्त करने वाली फर्मों का हिस्सा

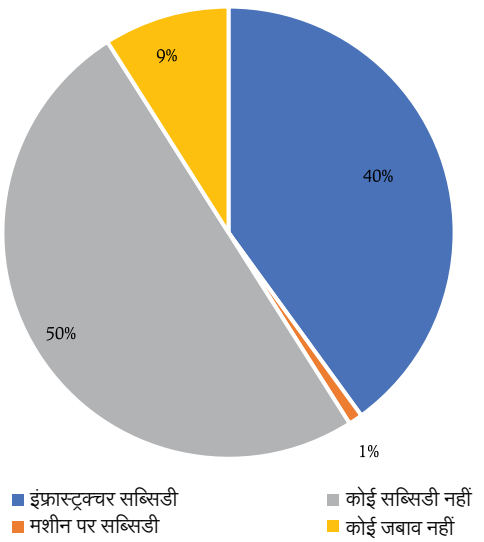

स्रोत : सर्वेक्षण पर आधारित लेखकों का अनुमान।

की कुल फर्मों में से पांचवां हिस्सा है और शेष फर्मों के पास 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर गोदाम सुविधा है।

भौतिक अवसंरचना[5] के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में, विभिन्न क्लस्टरों में लगभग 40 प्रतिशत फर्मों को किसी न किसी प्रकार की सब्सिडी मिली (चार्ट 8)। सब्सिडी पाने वाली फर्मों में से 43 प्रतिशत को बिजली, 29 प्रतिशत को पानी और 27 प्रतिशत को भूमि और इमारतों पर सब्सिडी मिली। लगभग 2 प्रतिशत फर्मों को तीनों सुविधाओं पर और 1 प्रतिशत को मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी मिली। लगभग 43 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु फर्मों को कम से कम एक सब्सिडी मिली, जबकि मध्यम उद्यमों में से केवल एक-पांचवें से भी कम को कम से कम एक सब्सिडी मिली।

III.3 डेटा आधारित निष्कर्ष

एमएसएमई क्षेत्र कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसमें राजस्व और उत्पादकता दोनों में गिरावट देखी गई है (यांगडोल और अन्य, 2023)। सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि 2022-23 और 2019-20 के बीच निवल लाभ मार्जिन (एनपीएम) में बदलाव के संदर्भ में, धातु, पहनने वाले परिधान और मोटर वाहनों ने वृद्धि दर्ज की, जबकि फार्मास्यूटिकल्स, लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर में 2019-20 के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 9)।

यह निर्धारित करने के लिए कि विभिन्न व्यय एमएसएमई इकाइयों के एनपीएम को कैसे प्रभावित करते हैं, हम लिंडमैन, मेरेंडा और गोल्ड (1980) द्वारा रैखिक मॉडल दृष्टिकोण में रिग्रॉसर के सापेक्ष महत्व का उपयोग करते हैं। यह पद्धति चयनित आश्रित चर में प्रत्येक व्याख्यात्मक चर के योगदान का पता लगाती है। *पी* रिग्रॉसर वाले रैखिक मॉडल के लिए,

चार्ट 9: कोविड-पूर्व (2019-20) की तुलना में कोविड-पश्चात (2022-23) निवल लाभ मार्जिन में परिवर्तन

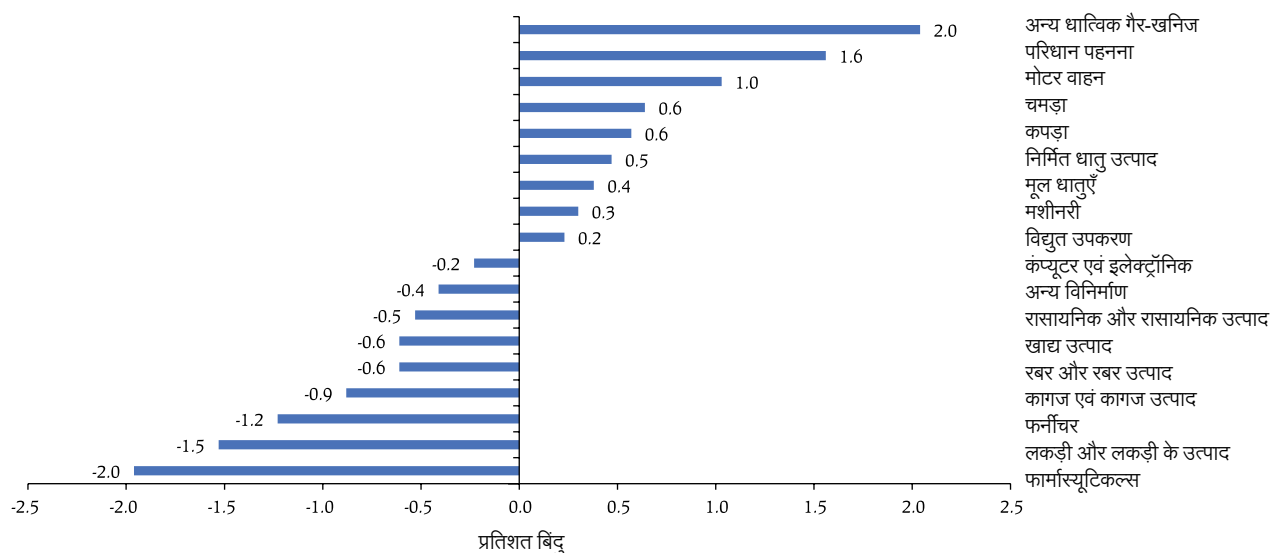

स्रोत : सर्वेक्षण पर आधारित लेखकों का अनुमान।

[5] बिजली, पानी, भूमि और भवनों के लिए प्राप्त सब्सिडी को अवसंरचना सब्सिडी माना जाता है।

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \ldots + \beta_p x_p + \epsilon \quad \ldots(1)$$

जहाँ y आश्रित चर है, x_is व्याख्यात्मक चर हैं और ϵ त्रुटि पद है जो मानक सामान्य वितरण का अनुसरण करता है। $R^2_{overall}$ प्रत्येक संकेतक द्वारा प्रत्यक्ष प्रभावों और समीकरण 1 में अन्य चरों के साथ संयुक्त प्रभावों पर विचार करते हुए आनुपातिक योगदान प्रदान करता है (पाल और भारती, 2019)। सभी व्याख्यात्मक चर इस R^2 समग्र में योगदान करते हैं। विचरण का विश्लेषण (एएनओवीए) भी सापेक्ष योगदान का अनुमान लगाता है; हालाँकि, यह व्याख्यात्मक चरों के क्रम के प्रति संवेदनशील है। लिंडमैन, मेरेंडा और गोल्ड (1980) दृष्टिकोण शेपली मूल्य पद्धति के आधार पर सभी ऑर्डर का अनुमान लगाता है। यह दृष्टिकोण एएनओवीए के मामले में सामने आए ऑर्डरिंग मुद्दे का ध्यान रखता है। इस विश्लेषण के लिए एनपीएम को आश्रित चर के रूप में उपयोग किया जाता है। यह जांचने के लिए कि क्या कुछ खर्चों के हिस्से में बढ़ोतरी ने एनपीएम को प्रभावित किया है अन्यथा, इसका मान 0 होगा.

चार्ट 10 परिणामों का सारांश दर्शाता है। किराया और बिजली खर्च को सर्वेक्षित एमएसएमई इकाइयों की लाभप्रदता के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में देखा जाता है, इसके बाद ऋण सेवा और कर्मचारियों के खर्च होते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कुछ क्लस्टरों में फर्मों को बिजली, भूमि या मशीनरी के लिए सरकारी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता मिल रही थी। फर्मों की लाभप्रदता पर इन वित्तीय प्रोत्साहनों के प्रभाव की जांच करने के लिए, अन्य प्रतिक्रिया चर के साथ-साथ राज्य और एमएसएमई क्लस्टरों के लिए क्लस्टर प्रभावों को शामिल करते हुए एक रैखिक मॉडल का उपयोग किया जाता है। वित्तीय सहायता की उपलब्धता के लिए फर्मों की प्रतिक्रिया के आधार पर, एक बाइनरी या डमी वैरिएबल बनाया गया है, यदि इकाई को किसी प्रकार की सब्सिडी मिली है तो मान 1 और अन्यथा 0 लिया गया है। इकाई का एनपीएम अभ्यास में आश्रित चर है। मॉडल के अनुमान में डमी नियंत्रण चर भी शामिल हैं, जिसमें आयु, कर्मचारी संख्या, उद्यम, ईएसआईसी, ईपीएफओ तक पहुंच और बैंक खाते के माध्यम से वेतन भुगतान के संबंध में औपचारिकता का स्तर शामिल है (हां के लिए, यह मान 1 लेता है, अन्यथा 0)। प्रतिगमन परिणाम बताते हैं कि सब्सिडी प्राप्त करने वाली एमएसएमई इकाइयों में उन लोगों की तुलना में अधिक एनपीएम था जिन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिली है। सब्सिडी के स्रोत के बावजूद परिणाम मोटे तौर पर सुसंगत रहते हैं (सारणी 3)।

चार्ट 10: निवल लाभ मार्जिन के महत्वपूर्ण निर्धारक

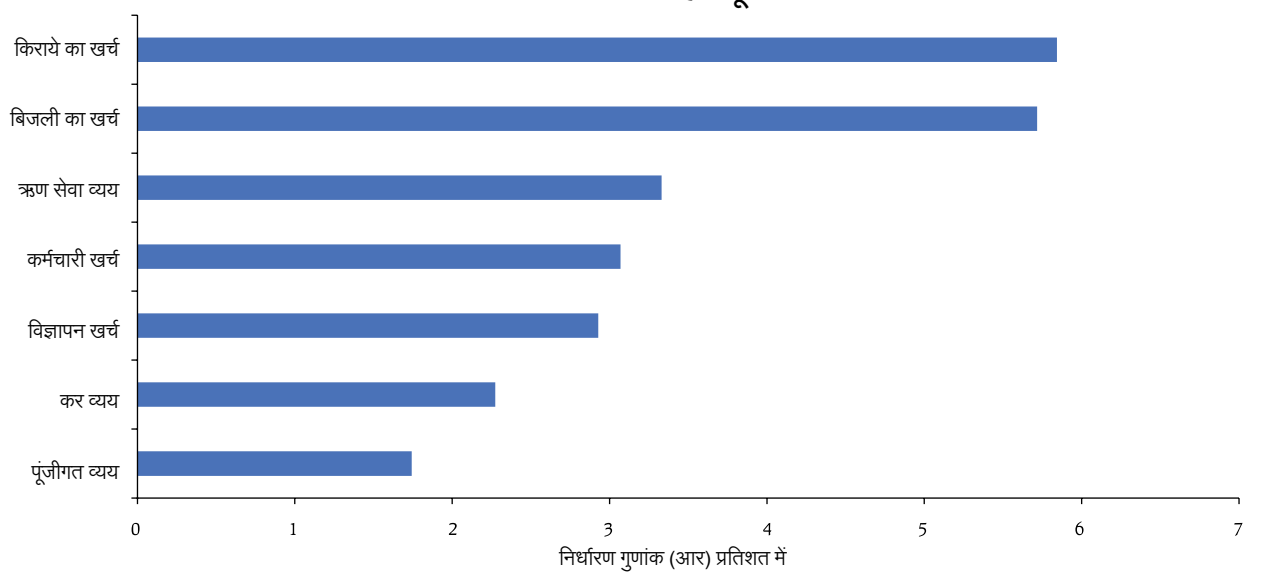

स्रोत : सर्वेक्षण पर आधारित लेखकों का अनुमान।

सारणी 3: फर्म की लाभप्रदता पर सब्सिडी का प्रभाव

	आश्रित चर = निवल लाभ मार्जिन (एनपीएम)		
	मॉडल 1	**मॉडल 2**	**मॉडल 3**
केंद्र सरकार की सब्सिडी	11.40 ** (3.90)		
राज्य सरकार की सब्सिडी		10.74 ** (3.68)	
केन्द्र एवं राज्य सरकार सब्सिडी			11.94 ** (4.11)
स्थिर	18.54 *** (1.65)	19.23 *** (1.64)	19.39 *** (1.76)
प्रेक्षणों की संख्या	1957	1957	1957
आर^2	0.18	0.15	0.16
राज्य और क्लस्टर निश्चित प्रभाव	Yes	Yes	Yes

टिप्पणी : मानक त्रुटियाँ कोष्ठक में हैं। * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01। अनुमान विभिन्न इकाई-विशिष्ट कारकों को नियंत्रित करता है, जिसमें आयु, कर्मचारी संख्या, उद्यम, ईएसआईसी, ईपीएफओ तक पहुँच और बैंक खाते के माध्यम से वेतन भुगतान शामिल हैं।
स्रोत : सर्वेक्षण के आधार पर लेखकों के अनुमान।

सारणी 4: ईसीएलजीएस कार्यान्वयन के बाद एमएसएमई के प्रदर्शन का अंतर-में-अंतर (डीआईडी) अनुमान

	निवल लाभ मार्जिन (एनपीएम)
वर्ष डमी	0.19** (0.0947)
ईसीएलजीएस डमी	6.96* (0.5435)
ईसीएलजीएस* वर्ष डमी	2.51* (0.2094)
आयु	-0.09* (0.0172)
एनआईसी डमी	Yes
स्थिर	14.2* (0.5347)
टिप्पणियों	8726
आर^2	0.15

टिप्पणी : 1. एनआईसी के लिए डमी का उपयोग किया गया है।
2. * और ** क्रमशः 1 और 5 प्रतिशत पर महत्व दर्शाते हैं।
3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
स्रोत : सर्वेक्षण के आधार पर लेखकों के अनुमान।

III.4 हालिया सरकारी योजनाएं और एमएसएमई

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से महामारी के बाद एमएसएमई के वित्तपोषण को आसान बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, 14 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से बड़ी फर्मों के साथ-साथ एमएसएमई को भी लाभ होता है। हमारे सर्वेक्षण में, एक-तिहाई उत्तरदाताओं ने विभिन्न योजनाओं पर प्रश्न का उत्तर दिया और इन उत्तरदाताओं में, ईसीएलजीएस को सबसे अधिक लाभकारी माना गया, उसके बाद मुद्रा, पीएलआई और टीआरईडीएस का स्थान रहा। ईसीएलजीएस के प्रभाव का और अधिक पता लगाने के लिए एनपीएम में अंतर-में-अंतर (डीआईडी) दृष्टिकोण लागू किया जाता है। यह एनपीएम को ईसीएलजीएस उपयोग के लिए डमी और किसी विशेष वर्ष से संबंधित इसकी अंतःक्रिया शर्तों के साथ आश्रित चर के रूप में उपयोग करता है (ईसीएलजीएस* वर्ष डमी)। 2022-23 के लिए एनपीएम पर ईसीएलजीएस के प्रभाव की जांच की जाती है। ईसीएलजीएस के प्रभाव का अनुमान लगाने में, ईसीएलजीएस में भाग लेने वाली फर्म उपचार फर्म हैं, जबकि अन्य फर्म नियंत्रण फर्म हैं। अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में प्रतिगमन में फर्म की आयु का भी उपयोग किया जाता है इस अभ्यास के लिए, निम्नलिखित समीकरण 2 का अनुमान लगाया गया है।

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \, ECLGS\ dummy_i + \beta_2 \, Year\ dummy_t + \delta \, (ECLGS\ dummy * Year\ dummy)_{it} + \varepsilon_{it} \quad ...(2)$$

ईसीएलजीएस, ईसीएलजीएस का सहारा लेने वाली फर्मों के लिए डमी वैरिएबल है। β_2 समय डमी है, जो 2021-22 के बाद के वर्ष के लिए मान 1 लेता है (हालाँकि ईसीएलजीएस 2020 में चालू है)। इंटरेक्शन टर्म *ईसीएलजीएस डमी* * वर्ष डमी है। *ईसीएलजीएस डमी* * वर्ष डमी का गुणांक ईसीएलजीएस के कार्यान्वयन के बाद एनपीएम पर ईसीएलजीएस के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करने वाला डीआईडी है।

डेटा आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि 2022-23 के दौरान सभी फर्मों के लिए औसत एनपीएम में वृद्धि हुई (सारणी 4)। इसके अलावा, इस योजना का लाभ न उठाने वाली फर्मों की तुलना में ईसीएलजीएस का सहारा लेने वाली फर्मों के लिए इसमें वृद्धि हुई, जैसा कि इंटरैक्शन टर्म के महत्व से संकेत मिलता है।

IV. निष्कर्ष

अध्ययन में भारत के विभिन्न क्लस्टरों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रदर्शन की जांच की गई। इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सूक्ष्म उद्यम शामिल थे, उसके बाद छोटे और मध्यम आकार

के उद्यम थे, जो विशिष्ट आर्थिक संरचना को दर्शाते थे। सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण किए गए क्लस्टरों में उत्तरदाता एमएसएमई के एक बड़े हिस्से ने पंजीकरण के माध्यम से अपने संचालन को औपचारिक रूप दिया है और विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। उत्तरदाता एमएसएमई का बहुमत बचत या प्रतिधारित लाभ जैसे आंतरिक स्रोतों पर निर्भर करता है, जबकि एक उल्लेखनीय अनुपात ने मुख्य रूप से बैंक ऋण और दीर्घकालिक वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से बाहरी वित्तपोषण का उपयोग किया है। अंतर-में-अंतर दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए एक डेटा आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि ईसीएलजीएस के तहत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली फर्मों ने सरकारी सहायता के बिना उन लोगों की तुलना में 2022-23 में उच्च एनपीएम प्रदर्शित किया। शोध पत्र के अवलोकन और परिणाम पूरे एमएसएमई क्षेत्र के लिए जरूरी नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान अध्ययन नमूना क्लस्टरों के भीतर एमएसएमई फर्मों तक सीमित है और क्लस्टरों के बाहर की फर्मों की विशेषताएं और व्यवहार अलग हो सकते हैं। कुल मिलाकर, एमएसएमई के लिए चल रही सहायता, विशेष रूप से भूमि, भवन और बिजली जैसी बुनियादी संरचना प्रदान करने में, महत्वपूर्ण है।

संदर्भ :

Dhawan, R. (2001). Firm size and productivity differential: theory and evidence from a panel of US firms. *Journal of Economic Behavior and Organization, 44*(3), 269-293. doi:10.1016/S0167-2681(00)00139-6.

GoI. (1997). Report of the Expert Committee on Small Enterprises (Chairman:Abid Hussain). Government of India.

GoI. (2014). *Understanding Innovation: Indian National Innovation Survey.* New Delhi: Department of Science and Technology, Government of India.

Haider, K., Khanna, M., Kotei, M., Kushnir, K., Singh, S. and Sridhar, T. (2019). *Micro, Small and Medium Enterprises-Economic Indicators (MSME-EI) : Analysis Note.* World Bank Group.

Krugman, P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. *Journal of Political Economy,99*(3),483-99. doi:abs/10.1086/261763#.

Lindeman, R. H., Merenda, P. F. and Gold, R. Z. (1980). *Introduction to bivariate and multivariate analysis.* Glenview, IL: Scott, Foresman.

Magar, S. (2017). Cluster Approach for Development of MSME Sector in India. *International Journal of Advanced Research, 5*(11), 414-420. doi:10.21474/IJAR01/5784.

Pachouri, A., Sharma, S. (2016). Barriers to Innovation in Indian Small and Medium-Sized Enterprises. *ADBI Working Paper 588.* doi:10.2139/ssrn.2838109.

Pal, M., Bharati, P. (2019). *Relative Contribution of Regressors. Applications of Regression Techniques*, 155-169. Singapore: Springer.

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. *Harvard Business Review, 68*(2), 73-93. Retrieved from https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations.

Porter, M. (1998). Clusters and New Economics of Competition. *Harvard Business Review, 76*(6), 77-90. Retrieved from https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition.

RBI. (2019). *Report of the Expert Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (Chairman:U K Sinha).* Reserve Bank of India.

UNIDO. (2020). *The UNIDO Approach to Cluster Development: Key Principles and Project Experiences.* Vienna: United Nations Industrial Development Organisation.

Utterback, J. (1994). *Mastering the Dynamics of Innovation.* Boston: Harvard Business School Press.

Williamson, O. (1967). Hierarchical control and optimum firm size. *Journal of Political Economy, 75*, 123-138. doi:abs/10.1086/259258.

Yangdol, R., Acharya, A. and Dhanya, V. (2023). COVID-19 and Productivity Performance of MSMEs and Large Firms in India. *Reserve Bank of India Occasional Papers, 44*(1).

अनुबंध

एमएसएमई सर्वेक्षण प्रश्नावली

क्लस्टर का नाम: _____ क्रमांक._____

दौरे की तिथि : _____ सर्वेक्षक का नाम: _____

1. फर्म का स्थान और प्रकृति:

स्थान/जिला	गांव शहर	राज्य	क्लस्टर का स्वामित्व	उद्यम का नाम और पता	उद्यम की ई-मेल आईडी और वेबसाइट
			केंद्र सरकार/राज्य सरकार/निजी क्षेत्र/सहयोगी		

2. कंपनी प्रोफाइल:

क्षेत्र	उत्पाद विवरण	एनआईसी कोड	उत्पाद का प्रकार (अंतिम/ मध्यवर्ती/ दोनों)	स्वामित्व का प्रकार (स्वामित्व/ साझेदारी/स्वयं सहायता समूह/ ट्रस्ट/निजी लिमिटेड)	कं. – सूचीबद्ध या असूचीबद्ध	क्या बैंक खाते रखे गए हैं	चाहे मौसमी परिचालन (हां/नहीं)	चाहे निर्यातोन्मुख हो या घरेलू
उत्पादन								
सेवाएं								

3. कंपनी ववरण

3.1. वित्तीय विवरण

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अपेक्षित)
बिक्री (लाख रुपए में)				
कर्मचारी (सं.)				
परिचालन लागत (सकल लाभ का %)				
निवल लाभ सीमा (%)				

3.2. निवेश और परिचालन का आकार (कृपया सही पर निशान लगाएं)

निवेश रुपये करोड़ में	वार्षिक कारोबार रुपये करोड़ में	कर्मचारियों की संख्या		स्थापना वर्ष/फर्म की आयु
		स्थायी	संविदात्मक	
< 1 करोड़	<5 करोड़			
< 10 करोड़	<50 करोड़			
<50 करोड़	<250 करोड़			
>50 करोड़	>250 करोड़			
वास्तविक राशि रु. में	वास्तविक राशि रु. में			

3.3. एमएसएमई का औपचारिकीकरण

क्या कंपनी उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत है?	हां नहीं
क्या आपके कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत हैं?	हां नहीं
क्या आपके कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में पंजीकृत हैं?	हां नहीं
क्या कंपनी कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन जमा करती है?	हां नहीं

3.4. कौशल के संदर्भ में श्रमिकों की संरचना और उनकी मजदूरी:

	कर्मचारियों की संख्या			प्रति माह औसत मजदूरी	
	स्थायी कर्मचारी	संविदा कर्मचारी	कुल कर्मचारी	स्थायी कर्मचारी	संविदा कर्मचारी
कुशल					
अर्द्ध कुशल					
अकुशल					
कुल					

4. क्लस्टर में सब्सिडी

4.1. क्लस्टर में बुनियादी ढांचा सुविधाएं/सब्सिडी

सब्सिडी (लागत के प्रतिशत के रूप में)	भूमि/भवन	बिजली	पानी	अन्य (कृपया बताएं)
75- 100 %				
50-75 %				
25- 50 %				
कोई सब्सिडी नहीं				

4.2. विनिर्माण इकाइयों से निम्नलिखित की दूरी (किमी में)

पत्तन	गोदाम	किनारा	रेलवे स्टेशन	सड़कें

5. बाज़ार (खरीद/बिक्री स्रोत)

5.1.आउटपुट की बिक्री/इनपुट की सोर्सिंग। कृपया हाँ/नहीं बताएँ और प्रत्येक के अंतर्गत साझा करें (प्रतिशत में)

	भारत में एक और एमएसएमई %	भारत के अंदर एकल बड़ी कॉर्पोरेट %	भारत के भीतर अनेक छोटे क्रेता/विक्रेता %	एक से अधिक बड़ी कम्पनियां	अधिकतर घरेलू, राज्य के भीतर या बाहर %	केवल राज्य के भीतर %	केवल निर्यात/ आयात %	अधिकतर निर्यात/आयात %
बेचा गया आउटपुट				%				
इनपुट/ कच्चा माल कहां से खरीदा गया								

5.2. **क्या उद्यम अनुबंध के आधार पर कोई कार्य करता है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो अनुबंध का प्रकार**

केवल अन्य उद्यम/ठेकेदार के लिए काम करना	
मुख्य रूप से अनुबंध के लिए, लेकिन अनुबंध के बिना अन्य ग्राहकों के लिए भी	
मुख्यतः बिना अनुबंध के, लेकिन अनुबंध पर भी काम करते हैं	

इनपुट का स्रोत (कृपया लागू करें पर टिक करें)

	स्वयं-प्राप्त	ठेकेदार द्वारा आपूर्ति	दोनों
उपकरण			
कच्चा माल			
उत्पाद का डिज़ाइन			
व्यापारिक उधार			

5.3. यदि निर्यातक उद्यम है तो कृपया विवरण दें?

प्रमुख गंतव्य देश	प्रमुख प्रतिस्पर्धी	क्या निर्यात गंतव्य एफटीए का हिस्सा है?	विनिमय दर जोखिम कवर (Y/N)

नोट : एफटीए- मुक्त व्यापार समझौता

5.4. क्या कच्चा माल बाहर से प्राप्त/आयात किया जाता है, हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया ब्यौरा दें।

प्रमुख स्रोत देश	आयातित कच्चे माल का प्रकार	एफटीए देशों से आयातित (हाँ/नहीं)	क्या विनिमय दर जोखिम कवर किया गया है (हां/नहीं)

5.5. यदि कच्चा माल बाहर से मंगाया जाता है तो कृपया ऐसा करने का कारण बताएं। (कृपया लागू पर निशान लगाएं)

कच्चे माल का नाम	लागत लाभ	बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पाद	विश्व स्तर पर स्थापित श्रृंखला	भारत में उपलब्ध नहीं है	अन्य (कृपया बताएं)

6. व्यापार का संचालन:

6.1. कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रमुख परिचालन व्यय

	बिजली	किराया	पूंजी की लागत	कर्मचारी लागत	करों	परिवहन	ऋण सेवा	विज्ञापन देना	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
कोविड-पूर्व									
कोविड के बाद									

6.2a. आपकी इकाई के सामने सबसे अधिक दबाव वाली व्यावसायिक समस्याएँ क्या हैं? (कृपया महत्व के अनुसार रैंक दें; समान रैंक भी दी जा सकती है) 5- सबसे महत्वपूर्ण, 4- महत्वपूर्ण, 3- कुछ हद तक महत्वपूर्ण, 2- महत्वपूर्ण नहीं, और 1- बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं।

	अन्य फर्मों से प्रतिस्पर्धा	जीएसटी	वित्त की कमी/ पहुंच	तकनीकी व्यवधान	बिजली की आपूर्ति	सरकारी मंजूरी	कुशल श्रम का अभाव	विनियामक अनुपालन	अन्य (कृपया बताएं)
कोविड-पूर्व									
कोविड-पश्चात									

6.2b. आपके व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आर्थिक मुद्दे क्या हैं? (कृपया महत्व के अनुसार रैंक दें; एक से अधिक के विरुद्ध भी समान रैंक दी जा सकती है) 5- सबसे महत्वपूर्ण, 4- महत्वपूर्ण, 3- कुछ हद तक महत्वपूर्ण, 2- महत्वपूर्ण नहीं, और 1- बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं।

	कीमतें कम करने का दबाव	इनपुट की बढ़ती कीमतें	मांग की कमी	उच्च श्रम लागत	कच्चे माल की कमी	वित्त की उपलब्धता	उच्च ब्याज दरें	उच्च विनिमय दरें	विदेशी प्रतिस्पर्धा
कोविड-पूर्व									
कोविड-पश्चात									

7. वित्त

7.1. कुल वित्त के प्रतिशत के रूप में आपकी फर्म के लिए वित्त का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? (कृपया महत्व के अनुसार रैंक करें) 5- सबसे महत्वपूर्ण, 4- महत्वपूर्ण, 3- कुछ हद तक महत्वपूर्ण, 2- महत्वपूर्ण नहीं, और 1- बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं।

	व्यापारिक उधार	प्रतिधारित कमाई	बैंक के ऋण	हिस्सेदारी	मित्र/ रिश्तेदार	निजी धन उधारदाता	एनबीएफसी	व्यक्तिगत संचय	फिनटेक	अन्य (कृपया बताएं)
कोविड-पूर्व										
कोविड के बाद										

नोट : फिनटेक का तात्पर्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म - भुगतान ऐप, बिजनेस-टू-बिजनेस लेंडिंग, पीयर-टू-पीयर लेंडिंग आदि के माध्यम से उधार लेना और देना है।

7.2. कुल वित्तपोषण में बैंक ऋण का हिस्सा

बैंक ऋण का हिस्सा	75-100%	50-75%	25-50%	>25%
कोविड-पूर्व				
कोविड-पश्चात				

7.3 ऋण का प्रकार

	सावधि ऋण		मांग ऋण (नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, खरीदे गए और भुनाए गए बिल आदि)
	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर	
कुल (बैंक और गैर-बैंक) ऋण पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी			
कुल बैंक ऋण में हिस्सा			

[6] मांग पर चुकाए जाने वाले सभी ऋण (जैसे नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, खरीदे और छूटे हुए बिल, आदि) और एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋण, चाहे सुरक्षित हों या असुरक्षित, मांग ऋण माने जाते हैं।

7.4. बकाया ऋण – मार्च 2023 तक

उधार का स्रोत	बकाया राशि (₹ लाख में)	देय ब्याज दर प्रति वर्ष
केंद्रीय/राज्य स्तरीय सावधि ऋण संस्थाएं		
सरकार		
वाणिज्यिक बैंक		
सहकारिता		
सूक्ष्म वित्त संस्थाएं		
अन्य संस्थागत एजेंसियां		
धन उधारदाता		
व्यावसायिक साझेदार		
आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार		
मित्र एवं रिश्तेदार		
अन्य		

7.5. क्या आपने अपनी परिसंपत्तियों/संयंत्रों/व्यवसाय का बीमा कराया है? हां नहीं

8. नवोन्मेष

8.1. उद्यम द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग पर विवरण।

	हाँ	नहीं
क्या उद्यम इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है?		
क्या सर्वेक्षण की तिथि पर उद्यम की वेब उपस्थिति है?		
क्या उद्यम को पिछले एक वर्ष के दौरान इंटरनेट या ईमेल के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं के लिए ऑर्डर प्राप्त हुए?		
कुल कर्मचारियों में से पिछले एक वर्ष के दौरान काम पर नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या		
क्या सर्वेक्षण की तिथि तक उद्यम के पास लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) है?		

8.2. क्या वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान प्रतिष्ठान ने निम्नलिखित में से कोई भी लागू किया है या उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है?

	हाँ	नहीं	अब नहीं करना	लागू नहीं होता
पैकेजिंग				
ब्रांडिंग/लोगो/नाम/ट्रेडमार्क				
उत्पाद का स्वरूप				
विज्ञापन के तरीके				
बिक्री चैनल या बिक्री बिंदु				
छूट योजनाएँ				
छूट के अलावा अन्य मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ				
भुगतान योजनाएं				
कर्मचारियों को नया प्रशिक्षण				

8.3. क्या फर्म ने कोविड के बाद की अवधि में कोई नई या उल्लेखनीय रूप से बेहतर प्रक्रिया/उत्पाद या सेवा शुरू की है? हाँ/नहीं/नहीं पता। यदि नहीं, तो प्रश्न संख्या 9 पर जाएँ।

8.4. यदि हां, तो कृपया विस्तार से बताएं कि नई प्रक्रिया/उत्पाद या सेवा इस प्रतिष्ठान द्वारा पहले उत्पादित सर्वाधिक समान उत्पाद या सेवा, यदि कोई हो, से किस प्रकार भिन्न है।.

	हाँ	नहीं	पता नहीं	ना
क्या इसमें कोई पूर्णतया नया कार्य है?				
क्या उत्पादन या पेशकश करना सस्ता है?				
क्या यह बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पाद या सेवा है?				
क्या यह अलग इनपुट का उपयोग करता है?				
क्या यह किसी ऐसी प्रौद्योगिकी या औद्योगिक डिजाइन पर आधारित है जिसका उपयोग इस प्रतिष्ठान द्वारा पहले नहीं किया गया है?				

8.5. नए उत्पाद/प्रक्रिया/सेवा को शुरू करने का कारण

	हाँ	नहीं	पता नहीं	ना
फर्म के किसी मौजूदा उत्पाद/प्रक्रिया/सेवा को प्रतिस्थापित करने के लिए				
फर्म के उत्पादों/प्रक्रिया/सेवा की सीमा का विस्तार करना				
नये बाजार खोलना और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना				
उत्पादन लागत कम करने के लिए				
प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए				
विनियमों या मानकों का अनुपालन करना				
अन्य उत्पादों/सेवाओं की मांग में कमी से निपटने के लिए				

9. कोविड-पश्चात

9.1. कोविड के बाद 2022 के दौरान कोविड-पूर्व अवधि की तुलना में निम्नलिखित संकेतकों ने कैसा प्रदर्शन किया है। (कृपया लागू होने वाले पर निशान लगाएँ)

	बिक्री		रोज़गार	मजदूरी लागत	इनपुट लागत	क्षमता उपयोग	वित्त की उपलब्धता
	घरेलू	निर्यात					
बढ़ा हुआ							
एक ही रुके							
में कमी							

9.2. आप आने वाले 3 वर्षों में अपने व्यवसाय के प्रदर्शन की क्या अपेक्षा रखते हैं? (कृपया लागू होने वाले पर निशान लगाएं)

	बिक्री राजस्व	इनपुट लागत	मुनाफे
काफी हद तक वृद्धि होगी			
सीमांत वृद्धि			
ऐसे ही रहना			
नीचे आ जाएगा.			

10. सरकारी योजनाएँ

10.1. राज्य/केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता का प्रकार (कृपया प्राप्त सभी का चयन करें) (उपयुक्त कॉलम पर निशान लगाएं)

	ऋण	सब्सिडी	मशीनरी /उपकरण	कौशल विकास	विपणन	कच्चा माल	निर्यात प्रोत्साहन	अन्य (कृपया बताएं)
केंद्र सरकार								
राज्य सरकार								

10.2. क्या सरकार से योजना/सब्सिडी का लाभ उठाया गया है (कृपया उपयोगिता के अनुसार योजना का आदेश दें)

योजनाओं	कृपया अपनी उपयोगिता के अनुसार योजना को रैंक करें (1 सर्वोच्च रैंक है)	किसी भी योजना के बारे में जानकारी नहीं	यदि नहीं, तो कृपया कारण बताएं
ईसीएलजीएस			
मुद्रा ऋण			
पीएलआई,			
टीआरईडीएस			
अन्य (कृपया बताएं)			

नोट : ईसीएलजीएस_आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, पीएलआई_उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, टीआरईडीएस_व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली।

10.3a. यदि हाँ, तो आप इन योजनाओं को कहाँ तक उपयोगी पाते हैं?

	बहुत उपयोगी	उपयोगी	उपयोगी नहीं	नहीं जानतीं
राजस्व में सुधार				
बिक्री की मात्रा/मात्रा में सुधार करने में				
कार्यशील पूंजी वित्त प्राप्त करना				
ऋण तक बेहतर पहुंच				

10.3b. यदि पी.एल.आई. का हिस्सा है, तो वृद्धिशील बिक्री का कितना प्रतिशत पी.एल.आई. को दिया जा सकता है।

>50%	25-50%	<25%	कोई परिवर्तन नहीं होता है

11. आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, वहां व्यवसाय विकास के लिए और क्या सहायता की आवश्यकता है?

कृपया निर्दिष्ट करें.....

12. कोई अन्य सुझाव: